RAJYA SABHA

The 5th September, 1970/the 14th Bhadra 1892 (Saka)

The house met at eleven of the clock, MR. CHAIRMAN in the Chair.

PAPERS LAID ON THE TABLE

I. ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS (1968-69) OF THE OIL AND NATURAL GAS COMMISSION AND RELATED PAPERS

II. ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS (1968) OF THE HYDROCARBONS INDIA PRIVATE LIMITED NEW DELHI AND RELATED PAPERS.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND MINES AND METALS (SHRI D. R. CHAVAN) : Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers :-

(i) Ninth Annual Report and Accounts of the Oil and Natural Gas Commission for the year 1968-69, together with the Audit Report thereon, under sub-section (3) of section 23 read with sub-section (4) of section 22 of the Oil and Natural Gas Commission Act, 1959.

(ii) Fourth Annual Report and Accounts of the Hydrocarbons India Private Limited, New Delhi, for the year 1968, together with the Auditors' Report on the Accounts.

(iii) Review by Government on the working of the companies mentioned at (i) and (ii) above.

[Placed in Library. *See* No. LT-4103/70 for (i) to (iii)]

ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS (FOR THE YEAR ENDED THE 30TH JUNE, 1969) OF THE AGRICULTURAL REFINANCE CORPORATION BOMBAY, AND RELATED PAPER (HINDI VERSION).

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R. GANESH) : Sir, I beg to lay on Table, under sub-section (2) of section 32 of the Agricultural Refinance Corporation Act, 1963, a copy of the Hindi Version of the Sixth Annual Report and Accounts of the Agricultural Refinance Corporation, Bombay for the year ended the 30th June, 1969, together with the Auditors' Report on the Accounts. [Placed in Library. *See* No. LT-4161/70]

REFERENCE TO FLOOD AND DROUGHT SITUATION IN BIHAR

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार). माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा भारत सरकार का ध्यान बिहार में बाढ़ और अकाल की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। श्रीमन्, 1967 में बिहार में भयंकर अकाल पड़ा था जो जग विख्यात है और उसके बाद 1970 में अकाल पड़ने जा रहा है। सरकार ने स्वीकार किया है कि 9½ लाख एकड़ भूमि पर फसल बरबाद हो चुकी है और 36 हजार वर्ग मील का एरिया बाढ़ में एफेक्टेड है और जो बचा हुआ क्षेत्र है वहां पर भी सूखे की स्थिति पैदा हो गई है। जिन क्षेत्रों में 25 प्रतिशत वर्षा हुई वह भी सूख रहे हैं। इस तरह से बिहार में बाढ़ और सूखे की स्थिति की वजह से अकाल की स्थिति बहुत ही भयंकर हो चुकी है। अगर सरकार इस मसले में पहले से ही ध्यान नहीं देगी तो हो सकता है कि वहां की जनता को भीषण अकाल का सामना करना पड़े। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह यह न सोचे कि जब विनाश की लीला अपना ताण्डव नृत्य कर लेगी तब सरकार ध्यान देगी, तो यह वहां की जनता के लिए उचित बात नहीं होगी।

केन्द्र की सरकार कहती है कि इस काम की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक प्रदेश सरकार की जिम्मे-

[श्री जगदम्बा प्रसाद यादव]

दारी का सवाल है उसके सीमित साधन है और वह इतनी बड़ी जिम्मेदारी को वहन नहीं कर सकती है।

आज बिहार प्रदेश की यह स्थिति है कि केन्द्रीय सरकार जब तक वहां पर अनेक वृहत योजनाएं शुरू नहीं करती, जब तक वहां पर निश्चित रूप से सिंचाई की योजनाएं नहीं होगी तब तक बराबर बिहार में अकाल पड़ता ही रहेगा और बिहार को अकाल से नहीं बचाया जा सकता है। कोसी की योजना अभी इतने वर्षों से पड़ी हुई है और वह अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। केन्द्र में इससे पूर्व जो सिंचाई मंत्री थे उन्होंने कहा था कि गंडक योजना को केन्द्र अपने हाथ में ले लेगी, लेकिन आज तक यह योजना केन्द्र ने अपने हाथ में नहीं ली है और यही कारण है कि आज तक यह योजना पूरी नहीं हो सकी है। केन्द्रीय सिंचाई उपमंत्री ने कहा था कि गंगा को बढ़ाकर दक्षिण में कावेरी तक ले जायेंगे, तो मैं उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि कम से कम गंगा का पानी का सदुपयोग बिहार में तो हो जाय और दक्षिण बिहार में जहां पर पानी की कमी रहती है इसके द्वारा पूर्ति हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि बिहार में भयंकर अकाल की स्थिति को देखते हुए वहां के वास्ते अविलम्ब व्यवस्था करनी चाहिये।

विपक्ष के नेता (**श्री श्यामनन्दन मिश्र**): चूंकि मैं भी इस सूबे से आता हूं इसलिए वहां की स्थिति के बारे में मुझे भी जानकारी है और मैं चाहता हूं कि उसे सदन के सामने निवेदन कर दूं। इस समय बिहार की स्थिति बड़ी गंभीर हो गई है। सभापति महोदय, जैसा आपको मालूम ही है कि बिहार को इस तरह की स्थिति का सामना पिछले कई सालों में करना पड़ा है और बिहार की आर्थिक अवस्था इसके कारण बहुत खराब हो गई है। वहां पर प्रति व्यक्ति की आय देश में सब से ज्यादा कम है। मेरा निवेदन यह है कि जिस तरह की स्थिति के आसार भविष्य में दिखलाई दे रहे है उसको देखते हुए केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि पूर्ण नियोजित ढंग से इसके बारे में कुछ करे। अगर आज से ही हम दृढ़ता के साथ एक योजना के आधार पर काम करेंगे तो वहां की स्थिति का मुकाबला करने में ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इसमें अगर माननीय सदस्यों के सहयोग की जरूरत है तो हम सभी इसमें अपेक्षित सहयोग देने के लिए तैयार है।

श्री भोला प्रसाद (बिहार): मैं इस संबंध में पहले भी सरकार का ध्यान दिला चुका हूं, लेकिन सरकार की ओर से, केन्द्रीय सरकार की ओर से अभी तक इस सम्बन्ध में बिहार में जो अकाल पड़ रहा है कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसलिए मेरा केन्द्रीय सरकार से निवेदन है कि वहां पर अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए उसे तीव्र गति से कदम उठाने चाहिये और खास तौर पर बिहार को अकाल से बचाने के लिए समुचित सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिये। इसके लिए कारगर कदम तत्काल उठाने के लिए अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। और अभी जिनने बड़े इलाके में यह फसल की बर्बादी हुई है सूखे और बाढ़ के चलते वहां लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए कम से कम 5 करोड़ रुपए की मदद नहीं की जायेगी तो लोगों को जो सहायता पहुंचाई जानी चाहिए वह नहीं पहुंच सकती है और बिहार सरकार उसको करने के लिए सक्षम नहीं है। दूसरी तरफ जो सिंचाई की योजनाएं है, जिन सिंचाई योजनाओं को लेने की बात की जा रही है उनमें अभी पश्चिमी कोसी नहर का मसाला नेपाल सरकार के साथ उस सम्बन्ध में फैसला नहीं हो जाने के कारण लटका हुआ है। वैसी सूरत में कहा जाता है कि दरभंगा के इलाके में बड़े पैमाने पर स्टेट ट्यूबवेल बैठाए जाएंगे। तो अभी तक जो योजना है वह महज चौथी पांच-साला योजना के अन्दर अगले साल एक हजार स्टेट ट्यूबवेल बैठाने की पूरे बिहार में है, परन्तु वह बहुत ही नाकाफी है। हमारा ख्याल है कि लगातार बिहार को जिस तरह अकाल में गुजरना पड़ रहा है प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक गांव में सबसे आसानी से और सबसे जल्दी स्टेट ट्यूबवेल के जरिए ही पानी पहुंचाने की गारन्टी की जा सकती है जिससे आगे फसल मारी न जा सके। और भी जो योजनाएं है, जिनके बारे में जिक्र वहां किया गया है, चाहे वह गंगा से लिफ्ट इरीगेशन की व्यवस्था हो या फिर . .

श्री सभापति अब आपने कह लिया, अब आप बन्द करिए।

श्री भोला प्रसाद: वह चौथी योजना में पूरी होनी चाहिए। इसकी ग्रान्ट केन्द्रीय सरकार की ओर से

जब तक नहीं आती है तब तक बिहार में वह योजना न ली जायगी, न पूरा होगी।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : श्रीमन्, मैं एक इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप सरकार को इसके लिए जवाब देने के लिए कहें, सरकार का ध्यान आकर्षित करें। सरकार जवाब देती नहीं है तो बात बढ़ती नहीं है।

REFERENCE TO PROGRAMME OF INDEFINITE "CEASE-WORK" BY TEACHERS OF AFFILIATED COLLEGES OF WEST BENGAL

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal) : Sir seven thousands teachers of the affiliated colleges of West Bengal have taken up a programme of indefinite "Cease work" from the 10th September, because they have failed to get the redressal of their long-standing demands. Sir, I understand that a delegation of these teachers with the Vice-Chancellor of the Calcutta University is currently in the capital, meeting the Government representatives, Education and other Ministers and I am told they have met even the Prime Minister and the Finance Minister also. Sir, now all I want to point out in this House, since we are coming to the end of this session, is that the Government should give some categorical assurance of financial assistance to them. Their main demand is that all the teachers including those who had come after 1966 should get the benefit of the revised pay. The only thing I want to point out is immediate fixation of pay in the new integrated pay scale on notional basis of the third Plan college teachers, new entrants and the teachers of 60-65 age group. This is the important, most important, demand. There are other demands, sixteen demands, enumerated in the documents that they placed before the Government. Sir, I think the Government should sympathetically consider—I am glad the Prime Minister is entering the House when I am making a reasonable demand on behalf of the Calcutta University colleges, affiliated colleges.

Sir, I understand they have met the Prime Minister. Their demand is very very reasonable. They want to get the benefit of the revised scales of pay which is being denied to them, a number of them—well, 7,000 or so are being denied.

Apart from this, there are other demands. It is a matter for the Ministry of Finance to make *ad hoc* grants or necessary assistance to the University authorities and I think the delegation has been brought here by the representatives of the teachers, headed by the Vice-Chancellor of the University. It should be given due weight and their demands should be accepted and the Government, in the interest of education, should give a categorical assurance that these will be met.

REFERENCE TO REBATE ON TEA EXPORTS

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान) : श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से एक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। गत वर्ष हमने अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए और उसको प्रोत्साहन देने के लिए एक रिबेट की स्कीम यहां पर स्वीकार की थी और जिन वस्तुओं पर रिबेट दिया जा रहा है चाय उन में से एक है। इसका उद्देश्य यह है कि जो फारेन परचेजर है उनको यह रिबेट मिले ताकि मार्केट में लोगों को हमारी चाय खरीदने के लिए उत्साह मिले और उसकी मार्केटिबिलिटी भी बढ़ सके। जो नान-कम्युनिस्ट कंट्रीज है उन के लिए तो इस रिबेट का कुछ अर्थ है, लेकिन कम्युनिस्ट कंट्रीज में, जहां स्टेट परचेजर है, वहां पर इस रिबेट का दुरुपयोग हो रहा है, जैसे यू०एस०एस०आर०। कोचीन के मार्केट में एक फर्म नव भारत इंटरप्राइजेज के नाम से यू०एस०एस०आर० वाले यह चाय खरीदते हैं और वह एक मात्र कस्टमर है इसकी शिपिंग के लिए भी। पिछले तीन महीनों में ही इस फर्म को इस रिबेट के तौर पर लगभग 8 या 9 लाख रुपया दिया हुआ है। मुझे यह जानकारी मिली है कि रूस इस रिबेट की रकम को प्राप्त करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो मैं यह चाहूंगा